



Neutral Citation No. - 2026:AHC:48102

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 552/2026

राजेश चौहान

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मनोज कुमार सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 54

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।
2. यह रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित राहत की मांग करते हुए दायर की गई है:-

"प्रतिवादियों को परमादेश की प्रकृति का एक रिट या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें उन्हें चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी द्वारा दिनांक 24/10/2024 को पारित आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया जाए; यह आदेश चकबंदी अधिकारी द्वारा भूखंड संख्या 392/1/-040 हेक्टेयर के संबंध में दिनांक 5.1.2023 को पारित आदेश के कार्यान्वयन के संदर्भ में दिया गया था।"

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. विस्तृत और समुचित विचार-विमर्श के पश्चात्, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मौखिक रूप से एक परमादेश रिट जारी करने का अनुरोध किया है, जिसमें चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी (संक्षेप में 'एसोसी') को निर्देश दिया जाए कि वे अपील संख्या 202354143600003448 (वर्ष 2023) का शीघ्रता से निस्तारण करें।

4. अभिलेख से प्राप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी संख्या 4 और 5 ने चक आवंटन की कार्यवाही प्रारंभ की थी; तथापि, उक्त कार्यवाही निरस्त कर दी गई थी। बाद के चरण में, उन्होंने 'उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, 1953' (संक्षेप में 'यूपीसीएच अधिनियम') की धारा 9-बी के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि भूखंड संख्या 392/1, जिसका क्षेत्रफल 0.040 हेक्टेयर है, को चकबंदी की कार्यवाही से बाहर रखा जाए, क्योंकि वह एक 'आबादी' (आवासीय क्षेत्र) है। चकबंदी अधिकारी ने दिनांक 08.07.2016 के आदेश के माध्यम से, यूपीसीएच अधिनियम की धारा 9-बी के तहत आपत्ति को स्वीकार कर लिया और परिणामस्वरूप, प्लॉट संख्या 392/1 (क्षेत्रफल 0.040 हेक्टेयर) को चकबंदी की कार्यवाही से बाहर रख दिया। इससे व्यथित होकर, वर्तमान याचिकाकर्ता ने एक बहाली याचिका दायर की। चकबंदी अधिकारी ने दिनांक 17.06.2017 के आदेश के माध्यम से, बहाली याचिका को स्वीकार कर लिया और दिनांक 08.07.2016 के आदेश को रद्द कर दिया; परिणामस्वरूप, यूपीसीएच अधिनियम की धारा 9-बी के तहत कार्यवाही को बहाल कर दिया गया। इससे व्यथित होकर, प्रतिवादी संख्या 4 और 5 ने दिनांक 17.06.2017 के आदेश के विरुद्ध एक बहाली याचिका दायर की। चकबंदी अधिकारी ने दिनांक 05.01.2023 के आदेश के माध्यम से, बहाली याचिका को खारिज कर दिया और दिनांक 17.06.2017 के आदेश की पुष्टि कर दी। इससे व्यथित होकर, विरोधी प्रतिवादियों ने उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 11(1) के तहत एसओसी, जौनपुर के समक्ष एक अपील दायर की है, जिसका अपील संख्या

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



202354143600003448/2023 है। अपील के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता ने एसओसी के समक्ष एक विविध याचिका प्रस्तुत की, जिसमें चकबंदी अभिलेखों में दिनांक 05.01.2023 के आदेश को लागू करने हेतु निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। एसओसी ने दिनांक 14.10.2024 की अपनी टिप्पणी के माध्यम से, उक्त याचिका के हाशिये पर यह निर्देश अंकित किया है कि चकबंदी अधिकारी दिनांक 05.01.2023 के आदेश को लागू करे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि चकबंदी की अनंतिम योजना के प्रकाशन के पश्चात्, चकबंदी की कार्यवाही के दौरान किए जाने वाले समस्त प्रासंगिक परिवर्तन 'सीएच पपत्र-23' में दर्ज किए जाते हैं।

5. अतः, मेरी राय में, एसओसी को अपील के त्वरित निस्तारण हेतु निर्देश जारी करना ही वर्तमान याचिकाकर्ता की शिकायत के निवारण के लिए पर्याप्त होगा।

6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर अपील के त्वरित निस्तारण हेतु निर्देश जारी किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

7. ऊपर बताए गए संदर्भ में, इस मामले को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए, यह न्यायालय वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा करना उचित समझता है; ऐसा करते समय न्यायालय याचिका में उठाए गए मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। न्यायालय प्रतिवादी संख्या 2 को यह निर्देश देता है कि वह संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, और किसी भी पक्ष को कोई अनावश्यक स्थगन दिए बिना, उपर्युक्त मामले का निर्णय पूरी तरह से कानून के अनुसार, एक तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश के माध्यम से, शीघ्रतापूर्वक करे—और

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अधिमानतः, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर ऐसा करे।

8. उपर्युक्त निर्देश के साथ, इस याचिका का अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)

10 मार्च, 2026

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”